जसबीर सिंह और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह से पहले, जे जे।

करतार कौर हालांकि एल.आर.एस.,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, - प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपीनं. 1983 का 2462

3 अगस्त, 2010

भारत का संविधान, i950-ए आरटी.226-भूमि अधिग्रहण ए सीआई, 1894-एस.एस. 4, 6 और 17 (एल)(सी) - उप-तहसील और अन्य कार्यालयों के लिए भवन के निर्माण के लिए तत्काल प्रावधानों को लागू करके भूमि अधिग्रहण की मांग की गई - धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के लगभग 2-'ए वर्षों के बाद चुनौती -अवार्ड पारित होने के बाद भी राज्य कब्ज़ा लेने में विफल रहा -अत्यावश्यकता खंड को लागू करना -अधिकारियों द्वारा अधिग्रहण के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफलता -धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करते समय राज्य के लिए अत्यावश्यक खंड को लागू करने का कोई अवसर नहीं, इस प्रकार, धारा 17 को लागू करने वाली अधिसूचना रद्द कर दी गई राज्य को कानून के अनुसार नए सिरे से भूमि अधिग्रहण के लिए आगे बढ़ने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए।

माना गया कि अधिनियम की धारा 17 (4) के साथ पठित धारा 4 के तहत अधिसूचना 10 सितंबर, 1981 को जारी की गई थी, लेकिन उसके बाद पुरस्कार केवल 7 मई, 1983 को पारित किया गया था। अजीब बात है कि, प्रावधानों को लागू करने के बावजूद भूमि का कब्ज़ा नहीं लिया गया था। अधिनियम की धारा 17 का. इतना ही नहीं अवार्ड पारित होने के बाद भी कब्जा नहीं लिया गया। याचिकाकर्ता ने 17 मई, 1983 को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जब इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता की बेदखली पर रोक लगा दी गई। उत्तरदाताओं द्वारा इस बात पर कोई विवाद नहीं किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित होने की तिथि तक, उनके द्वारा कब्ज़ा नहीं लिया गया था। यह स्वयं ही बोलता है और किसी और स्पष्टीकरण या औचित्य की आवश्यकता नहीं है। अधिग्रहण की कार्यवाही को अंतिम रूप देने में देरी के लिए एकमात्र स्पष्टीकरण यह दिया गया है कि उप-तहसील, गन्नौर को पूर्ण तहसील स्तर का दर्जा दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप अधिक अधिग्रहण के प्रस्ताव पर पुनर्विचार हुआ और अंततः यह निर्णय लिया गया कि वे इसे जारी रखेंगे। अधिग्रहण के लिए पूर्व अधिसूचना और अधिग्रहीत की जाने वाली अतिरिक्त भूमि के लिए अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत नई अधिसूचना जारी करें। यह रिकॉर्ड पर नहीं आया है और न ही प्रतिवादियों के वकील अदालत को यह बता सके कि आगे जमीन दी गई है या नहीं

#

उत्तरदाताओं द्वारा अर्जित किया गया या इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है या नहीं। हालाँकि, उत्तरदाताओं की ओर से बाद में की गई निष्क्रियता अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में अधिकारियों द्वारा दिमाग का उपयोग न करने को और मजबूत करती है। अधिनियम की धारा 17 के तहत क़ानून के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उत्तरदाताओं द्वारा ईमानदारी से नहीं किया गया है , बल्कि इसे सबसे आकस्मिक और गैर-जिम्मेदाराना तरीके से लागू किया गया है। अत्यावश्यक धारा को लागू करते समय, राज्य को वास्तव में उचित देखभाल और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। 'अत्यावश्यक धारा का प्रयोग राज्य प्रशासन की ओर से ढिलाई या सुस्ती या देखभाल की कमी का विकल्प या समर्थन नहीं हो सकता है। अधिकारियों द्वारा अधिग्रहण के लिए समय पर कार्रवाई करने या अधिग्रहण की कार्यवाही को पूरा करने में विफलता आवश्यकता और तात्कालिकता को दर्शाती है जो अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रावधानों को लागू करने का कारण थी।

इसके अलावा, यह माना गया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 17(1)(सी) के तहत तत्काल प्रावधानों को लागू करना उचित नहीं था। इसलिए, अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही को कानून के अनुसार नहीं कहा जा सकता है और तदनुसार याचिकाकर्ता को रद्द किया जाना चाहिए।

(पैरा 9)

इसके अलावा, गन्नौर में उप-तहसील भवन और अन्य कार्यालयों के भवन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता बताई गई। त्चसील और जिला सोनीपत। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए था और वह उद्देश्य अभी भी अस्तित्व में है। इसलिए, अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना को रद्द करने का कोई इरादा नहीं है। हम हालाँकि, यह मानते हैं कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करते समय राज्य के पास अत्यावश्यक खंड को लागू करने का कोई अवसर नहीं था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के आधार पर अधिनियम की धारा ।7 को लागू करने वाली अधिसूचना रद्द की जाती है । यदि यह ऐसा निर्णय लेता है स्टेल याचिकाकर्ता से नई आपत्ति मांगने और अधिनियम के तहत प्रदान की गई उचित प्रक्रिया का पालन करके उस पर विचार करने और कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण करने के लिए आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा।

(पैरा 10)

वी.के.लेन. वरिष्ठ अधिवक्ता जेके भट्टी के साथ। वकील। याचिकाकर्ता जार

कमल सहगल. अतिरिक्त. एजी. 1 लारियाना./ डॉ. उत्तरदाता।

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.

(1) इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के साथ पठित धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 1 सितंबर, 1981 (अनुलग्नक पी-1) को चुनौती दी है। अधिनियम की धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 11 सितंबर, 1981 (अनुलग्नक पी-3), - जिसके तहत याचिकाकर्ता की आयत संख्या 39, खसरा संख्या 4/2 और 4/3 में आने वाली भूमि गन्नौर गांव तहसील एवं जिला सोनीपत में स्थित है का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया गया था।

(2) याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत उपधारा (2) के खंड (सी) और धारा 17 की उपधारा (4) के प्रावधानों को लागू करके जारी की गई अधिसूचना गलत इरादे से है। याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 5-ए के तहत दिए गए सुनवाई के अधिकार से वंचित करें जिसके तहत वह प्रस्तावित अधिग्रहण पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने की हकदार थी। तात्कालिक प्रावधानों को लागू करके, उत्तरदाताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत प्रदत्त उसके मूल्यवान अधिकार को छीन लिया है, जो एक मौलिक अधिकार के समान है और उक्त अधिकार को केवल असाधारण परिस्थितियों और तात्कालिक मामलों में ही कम किया जा सकता है। जहां कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती. वर्तमान मामले में, गन्नौर, तहसील और जिला सोनीपत में उप-तहसील भवन और अन्य कार्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जो ऐसी प्रकृति की नहीं थी कि इसमें 30 दिनों की देरी का इंतजार नहीं किया जा सकता था। याचिकाकर्ता के अधिनियम की धारा 5-ए के तहत प्रदान की गई आपत्तियों पर विचार और निर्णय नहीं किया जा सकता था। वास्तव में, 1.1 सितंबर 1981 को धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद डेढ़ साल के अंतराल के बाद अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस जारी किया गया था जो स्वयं बताता है कि इसे लागू करने की कोई तात्कालिकता नहीं थी। अधिनियम की धारा 17(2)(सी) के प्रावधान। यह पुरस्कार 7 मई, 1983 को पारित किया गया था। यह तात्कालिकता खंड को लागू करके उत्तरदाताओं द्वारा शक्तियों के अवैध प्रयोग को साबित करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना प्रेरित थी और केवल कीमतें बढ़ाने के लिए जारी की गई थी और जिस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उसके लिए कोई त्वरित निष्पादन नहीं था। अधिग्रहण की कार्यवाही को अंतिम रूप देने में अस्पष्ट देरी से पता चलता है कि जिस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था, वह अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के दायरे में नहीं आएगा। प्रतिकृति का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि वास्तव में आधारशिला 20 जनवरी, 1 को रखी गई थी ! हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा 990 एवं

उद्घाटन समारोह 29 मार्च 1991 को आयोजित किया गया था। इस आधार पर उनका मानना है कि अधिनियम की धारा 17 (2)(सी) और (4) के तहत प्रावधानों को लागू करना कानून के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना 1 सितंबर, 1981

को जारी की गई थी जो 14 सितंबर को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। 1981 और 12 अक्टूबर 1981 को इलाके में सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था और इस तरह अधिसूचना के सार को प्रकाशित करने में 29 दिनों की देरी हुई, जो स्वयं उत्तरदाताओं के संवेदनहीन रवैये को दर्शाता है। किसी भी मामले में, उनका कहना है कि अधिसूचना और सार्वजनिक नोटिस का प्रकाशन एक साथ इलाके में किया जाना आवश्यक था और अकेले इस स्कोर पर, यह अधिसूचना रद्द करने योग्य है। अधिनियम की धारा 5-ए के अनुसार, अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। याचिकाकर्ता ने 1 नवंबर, 1981 को अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियां प्रस्तुत की थीं, जिन पर उत्तरदाताओं द्वारा विचार नहीं किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता से कब्ज़ा नहीं लिया गया था, इसलिए, याचिकाकर्ता इस धारणा पर आगे बढ़ा था कि आपत्तियों को उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और इसलिए, इस वास्तविक विश्वास के तहत, अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाओं को चुनौती नहीं दी गई थी। . उनका कहना है कि पुरस्कार 7 मई, 1983 को पारित किया गया था और वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा 16 मई, 1983 को तुरंत दायर की गई थी, जो 17 मई, 1983 को इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी, जब याचिकाकर्ता की बेदखली पर रोक लगा दी गई थी। इसलिए, उनका तर्क है कि धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाएं और उससे उत्पन्न होने वाली सभी आगामी कार्यवाहियां रद्द कर दी जाएं। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने ओम प्रकाश और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य (1) भारत संघ और अन्य बनाम कृष्ण लाल अर्न्जा और अन्य (2) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है। भारत संघ और अन्य बनाम मुकेश हंस आदि (3) गुरचरण सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (4) मुरारी लाल गुप्ता बनाम पंजाब राज्य और अन्य (5) और रतन सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (6)

3) दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य के वकील का तर्क है कि वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा विलंब से दायर की गई है। उनका कहना है कि धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाएँ क्रमशः 1 सितंबर, 1981 और 11 सितंबर, 1981 को जारी की गईं थीं। याचिकाकर्ता ने पुरस्कार पारित होने तक इंतजार किया और 16 मई, 1983 को रिट याचिका दायर की। यदि उसे अधिसूचनाओं के खिलाफ कोई शिकायत थी, तो उसे तुरंत इस न्यायालय में रिट याचिका दायर करके उन्हें चुनौती देनी चाहिए थी। उनका तर्क है कि 7 मई, 1983 को पुरस्कार पारित होने के बाद, अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी हो गई और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सका। इस तर्क के समर्थन में, वह हरि सिंह और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य, (7) और स्वर्ण लता आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (8) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हैं।). उन्होंने आगे कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत आदेश यह नहीं है कि अधिसूचना प्रकाशित की जाए और उसकी सामग्री को एक साथ इलाके में सार्वजनिक किया जाए। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने इस बात पर विवाद किया है कि ऐसा प्रकाशन किया गया था, और इसलिए, कानून की आवश्यकता का पूरी तरह से पालन किया गया। अधिनियम की धारा 17(2)(सी)(4) के प्रावधानों को लागू करने के

संबंध में, उनका तर्क है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उप-तहसील के भवन के निर्माण के लिए अधिग्रहण की तत्काल आवश्यकता थी। अन्य भूस्वामियों की भूमि के साथ याचिकाकर्ता की भूमि को उपयुक्त माना गया और इसलिए उचित विचार के बाद उक्त उद्देश्य के लिए चुना गया। अधिग्रहण की कार्यवाही को अंतिम रूप देने में देरी के संबंध में, उनका तर्क है कि उप-तहसील, गन्नौर का दर्जा 1 अप्रैल, 1982 को पूर्ण तहसील के स्तर तक बढ़ा दिया गया था, जब अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही थी, जिसके कारण अधिक भूमि की आवश्यकता थी। भवन के निर्माण के लिए मामले पर पुनर्विचार किया गया जिसके परिणामस्वरूप देरी हुई। हालाँकि, यह निर्णय लिया गया कि उप-तहसील, गन्नौर के निर्माण के लिए भूमि के संबंध में अधिग्रहण की कार्यवाही जारी रखी जाएगी और पूरी की जाएगी और अतिरिक्त भूमि के लिए नई अधिसूचनाएँ जारी की जाएंगी। वकील निर्माण शुरू करने की प्रक्रिया में देरी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए दावों की प्रतिकृति में कहा गया है, याचिकाकर्ता द्वारा एक बयान दिया गया था। कि आधारशिला 20 जनवरी 1990 को रखी गई थी यानी 7 मई 1983 को पुरस्कार पारित होने के 8 साल की देरी के बाद उन्होंने आगे तर्क दिया कि अधिसूचना और सार्वजनिक नोटिस जारी करने से याचिकाकर्ता के साथ कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है। इलाके में इस कारण से हंगामा हुआ कि अधिनियम की धारा 17(2)(सी) और (4) के प्रावधानों को लागू करने से, याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 5-ए के तहत कोई आपत्ति दर्ज करने का हकदार नहीं था। सरकार द्वारा कानून के अनुसार छूट दी गई है। तदनुसार, वह प्रार्थना करते हैं कि वर्तमान रिट याचिका में कोई दम नहीं है और यह खारिज किये जाने योग्य है।

(4) हमने पक्षों के वकीलों को सुना है और मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(5) इस स्तर पर पहला प्रश्न जिसका उत्तर देने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या वर्तमान याचिका उत्तरदाताओं के वकील द्वारा उठाई गई आपत्तियों के आलोक में सुनवाई योग्य है कि याचिकाकर्ता ने जारी होने के लगभग ढाई साल की देरी के बाद इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना और पुरस्कार पारित होने के बाद भी। माना जाता है कि अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचना 1 सितंबर, 1981 को जारी की गई थी और उसके सार को 18 सितंबर, 1981 और 11 सितंबर, 1981 को इलाके में सार्वजनिक किया गया था और उसके सार को 12 सितंबर को इलाके में सार्वजनिक किया गया था। क्रमशः अक्टूबर, 1981। याचिकाकर्ता ने 1 नवंबर, 1981 को अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कीं। उस पर कोई निर्णय उन्हें नहीं बताया गया और न ही भूमि का कब्ज़ा लिया गया। इस वास्तविक विश्वास के तहत कि उसकी आपत्तियों को उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, याचिकाकर्ता ने अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी। 7 मई, 1983 को पुरस्कार पारित होने के बाद ही उन्हें पता चला कि उत्तरदाता अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसने तुरंत इस न्यायालय से संपर्क किया और 16 मई, 1983 को वर्तमान रिट याचिका दायर की, जो 17 मई, 1983 को सुनवाई के लिए आई जब इस न्यायालय द्वारा उसकी बेदखली पर रोक लगाने का आदेश पारित किया गया। हरि सिंह के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय में आने में देरी के संबंध में अपने तर्क

पर जोर देने के लिए उत्तरदाताओं के वकील ने जिस फैसले पर भरोसा किया है। विशिष्ट विशेषता यह है कि स्लेट द्वारा अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों को लागू करने पर, भूमि का कब्ज़ा अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा तुरंत ले लिया गया था। उन्हीं के तहत परिस्थितियों के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 4 और धारा 17 के तहत अधिसूचना जारी होने की तारीख से ढाई साल की देरी के बाद कार्यवाही को चुनौती दी गई है, रिट याचिका खारिज की जा सकती है। . मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता की बेदखली पर रोक लगने की तारीख तक अवार्ड पारित होने के बाद भी कब्जा नहीं लिया गया था। इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पहले प्रतिवादियों द्वारा कब्जा नहीं लेने का तथ्य विवाद में नहीं है। स्वर्ण लता के मामले (सुप्रा) में भी, यह एक ऐसा मामला था जहां अवार्ड पारित होने और कब्ज़ा लेने के बाद अधिसूचना को रद्द करने के लिए रिट याचिका दायर की गई थी। वहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि पुरस्कार पारित होने के बाद कब्ज़ा लेने पर, भूमि अधिनियम की धारा 16 के तहत सरकार में निहित हो जाती है, सभी बाधाओं से मुक्त हो जाती है और इसलिए, धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचना जारी की जाती है। उस विलम्बित चरण में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसलिए, ये निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं, जहां निर्णय पारित होने और उसके 10 दिन बाद भी उत्तरदाताओं द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है। तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका को सुनवाई योग्य माना जाता है।

(6) याचिकाकर्ता के वकील का यह तर्क कि अधिसूचना का प्रकाशन और इलाके में सार्वजनिक नोटिस एक साथ होना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 4 के तहत ऐसा कोई आदेश नहीं है। यह केवल आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान करता है और कलेक्टर को उस समय लागू असंशोधित प्रावधानों के तहत उक्त इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर ऐसी अधिसूचना के सार की सार्वजनिक सूचना देने का आदेश देता है। रतन सिंह के मामले (सुप्रा) में याचिकाकर्ता के वकील ने जिस फैसले पर भरोसा किया, वह पूर्ण रूप से समान नहीं है। चूंकि अधिनियम की धारा 4(1) में उल्लिखित दोनों शर्तों का अनुपालन किया गया है, इसलिए अधिनियम की धारा 4 के तहत उक्त अधिसूचना को कानून के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है।

(7) अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि अधिनियम की धारा 5-ए उस व्यक्ति के पक्ष में एक मूल्यवान अधिकार प्रदान करती है जिसकी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है क्योंकि राज्य द्वारा 'प्रख्यात डोमेन' की अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसे उसकी संपत्ति से वंचित किया जा रहा है। शक्ति के ऐसे प्रयोग पर आपत्ति जताने के लिए और कब विचार किया जाए भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत निहित प्रावधानों के संदर्भ में और उन्हें ध्यान में रखते हुए, जो मौलिक अधिकार के समान है, धारा के प्रावधानों को लागू करके राज्य द्वारा बिना किसी औचित्य और उचित विचार के मौलिक अधिकार से इनकार किया जाता है। अधिनियम की धारा 17 पूर्णतः अनावश्यक है। प्रत्येक अधिग्रहण में जहां अधिनियम की धारा 17 लागू की जाती है, वहां भूमि अधिग्रहण की तत्काल आवश्यकता होती है, जहां देरी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहां ऐसी स्थिति मौजूद नहीं है, अधिनियम की धारा 5-ए के तहत अधिकार

से इनकार करने से भूमि मालिकों के साथ अन्याय होगा। अधिनियम की धारा 17 प्राधिकरण को एक असाधारण शक्ति प्रदान करती है जिसके तहत वह अधिनियम की धारा 5-ए के तहत निर्धारित सामान्य प्रक्रिया से छूट दे सकती है। ऐसी शक्ति का हल्के ढंग से सहारा नहीं लिया जा सकता है - वास्तविक आपातकाल के मामले को छोड़कर जो सरकार को उस भूमि पर तत्काल कब्ज़ा करने में सक्षम बनाती है जिसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है। प्राधिकरण को सार्वजनिक उद्देश्य की प्रकृति, स्थिति की मांग के अनुसार वास्तविक तात्कालिकता और स्पष्ट रूप से समय कारक को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 17 के तहत तात्कालिकता खंड को लागू करने की आवश्यकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना होगा। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि संपत्ति का कब्ज़ा लेने के लिए उस न्यूनतम अवधि की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती जिसके भीतर भूमि मालिकों से आपत्तियां प्राप्त की जा सकें और अधिनियम की धारा 5-ए के तहत जांच पूरी की जा सके। इसलिए, कसौटी यह होनी चाहिए कि कब्जा लेने में देरी होने की स्थिति में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण का मूल उद्देश्य शून्य हो जाएगा या निराश हो जाएगा या निरर्थक हो जाएगा। इन असाधारण और असाधारण परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 17 के अत्यावश्यक खंड को लागू करना आवश्यक है। इसका सहारा केवल क़ानून के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया और प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 5-ए निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को प्रस्तावित अधिग्रहण पर आपत्तियां दर्ज करने का अधिकार प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 5-ए के तहत प्रतिनिधित्व का अधिकार इस उद्देश्य से है कि जिस व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाना है, उसे संबंधित अधिकारियों को यह समझाने का उचित और उचित अवसर मिलना चाहिए कि उसकी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि उपयुक्त सरकार इस मूल्यवान अधिकार को छीनने का निर्णय लेती है, तो ऐसा करने का उसका निर्णय भौतिक कारणों पर आधारित होना चाहिए जो कि प्रावधानों को लागू करने को उचित ठहराए।अधिनियम की धारा 17. प्राधिकरण को अधिनियम की धारा 5-ए के उद्देश्य और उद्देश्य को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। केवल अधिनियम की धारा 17 को लागू करके अधिसूचना जारी करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसके बाद की गई कार्रवाई भी कारण की तात्कालिकता और प्राधिकरण के निर्णय को उचित ठहराने और समर्थन करने के लिए उसी दिशा में आगे बढ़नी चाहिए।

(8) मौजूदा मामले में, अधिनियम की धारा 17(4) के साथ पठित धारा 4 के तहत अधिसूचना 1 सितंबर, 1981 को जारी की गई थी और धारा 6 अधिसूचना 11 सितंबर, 1981 को जारी की गई थी, लेकिन उसके बाद पुरस्कार केवल 7 मई, 1983 को पारित किया गया था। अजीब बात है कि अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों को लागू करने के बावजूद भूमि पर कब्ज़ा नहीं किया गया। इतना ही नहीं अवार्ड पारित होने के बाद भी कब्जा नहीं लिया गया। याचिकाकर्ता ने 17 मई, 1983 को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जब इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता की बेदखली पर रोक लगा दी गई। उत्तरदाताओं द्वारा इस बात पर कोई विवाद नहीं किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित होने की तिथि तक, उनके द्वारा कब्ज़ा नहीं लिया गया था। यह स्वयं ही बोलता है और किसी और स्पष्टीकरण या औचित्य की आवश्यकता नहीं

है। अधिग्रहण की कार्यवाही को अंतिम रूप देने में देरी के लिए एकमात्र स्पष्टीकरण यह दिया गया है कि उपतहसील, गन्नौर को पूर्ण तहसील स्तर का दर्जा दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप अधिक भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव पर पुनर्विचार हुआ और अंततः यह निर्णय लिया गया कि वे इसे जारी रखेंगे। अधिग्रहण के लिए पूर्व अधिसूचना और अधिग्रहीत की जाने वाली अतिरिक्त भूमि के लिए अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत नई अधिसूचना जारी करें। यह रिकॉर्ड पर नहीं आया है और न ही उत्तरदाताओं के वकील अदालत को सूचित कर सके कि क्या उत्तरदाताओं द्वारा आगे की भूमि का अधिग्रहण किया गया है या इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है या नहीं। हालाँकि, उत्तरदाताओं की ओर से बाद में की गई निष्क्रियता अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में अधिकारियों द्वारा विवेक का प्रयोग न करने को और मजबूत करती है। जैसा कि प्रतिकृति के माध्यम से रिकॉर्ड में लाया गया है कि 7 मई, 1983 को पुरस्कार की घोषणा के बाद, भवन की आधारशिला 20 जनवरी, 1990 को रखी गई थी और भवन पूरा हो गया और 29 मार्च, 1991 को उद्घाटन किया गया जो लगभग है जारी होने की तिथि से साढ़े नौ वर्ष। अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना। अधिनियम की धारा 17 के तहत क़ानून के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उत्तरदाताओं द्वारा ईमानदारी से नहीं किया गया है , बल्कि इसे बहुत ही आकस्मिक तरीके से लागू किया गया है। गैरजिम्मेदाराना ढंग. अत्यावश्यक धारा को लागू करते समय, राज्य को वास्तव में उचित देखभाल और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। अत्यावश्यक धारा को लागू करना राज्य प्रशासन की ओर से ढिलाई या सुस्ती या देखभाल की कमी का विकल्प या समर्थन नहीं हो सकता है। अधिकारियों द्वारा अधिग्रहण के लिए समय पर कार्रवाई करने या अधिग्रहण की कार्यवाही को पूरा करने में विफलता आवश्यकता और तात्कालिकता को दर्शाती है जो अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रावधानों को लागू करने का कारण थी। ओम प्रकाश के मामले (सुप्रा) में , माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जहां अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने में एक वर्ष से अधिक की देरी हुई थी, धारा 17 (4) के साथ पठित धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद) अधिनियम का और उत्तरदाताओं के आचरण के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, यह अधिग्रहण की तात्कालिकता के उनके दावे को गलत साबित करता है और तदनुसार अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों को लागू करना राज्य द्वारा अवैध माना गया था।

(9) उपरोक्त के मद्देनजर, हमारी राय है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 17(1)(सी) के तहत तत्काल प्रावधानों को लागू करना उचित नहीं था। इसलिए, अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही को कानून के अनुसार नहीं कहा जा सकता है और तदनुसार याचिकाकर्ता को रद्द किया जाना चाहिए।

(10) हम इस बात से संतुष्ट हैं कि गन्नौर, तहसील और जिला सोनीपत में उप-तहसील भवन और अन्य कार्यालयों के लिए भवन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता सार्वजनिक उद्देश्य के लिए थी और वह उद्देश्य अभी भी अस्तित्व में है और इसलिए, नहीं है अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना को रद्द करने के इच्छुक हैं। हालाँकि, हम मानते हैं कि राज्य के

पास अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करते समय अत्यावश्यक खंड को लागू करने का कोई अवसर नहीं था और इस प्रकार, याचिकाकर्ता के लिए अधिनियम की धारा 17 को लागू करने वाली अधिसूचना को रद्द किया जाता है। राज्य याचिकाकर्ता से नई आपत्ति मांगने और अधिनियम के तहत प्रदान की गई उचित प्रक्रिया का पालन करके उस पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगा और यदि वह निर्णय लेता है तो कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(11) वर्तमान रिट याचिका उपरोक्त शर्तों में स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कैथल, हरियाणा